MR. DEPUTY-SPEAKER : The result * of the division is : Ayes : 28 ; Noes : 63.

The motion was negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall now put the other Cut Motions to the vote of the House...

SHRI KANWAR LAL GUPTA : Cut Motion 5 is an important one...

MR. DEPUTY-SPEAKER : This is not the procedure that we follow. Every time you come late. I waived the time-limit. Again you are coming late.

I will now put the other Cut Motions to the vote of the House.

All other Cut Motions were put and negatived.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That the respective Supplementary sums not exceeding the amounts shown in the third column of the order paper be granted to the President to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1969, in respect of the following demands entered in the second column thereof.

Demand Nos. 1, 3 to 8, 13 to 15, 18, 20, 21, 23, 24, 27, 30, 34, 35, 38, 41, 45, 46, 48, 49, 52 to 58, 60, 66, 69, 70, 72, 75 to 77, 79, to 81, 84, 85, 93, 96, 110, 113, 115, 119, 121, 123, to 125, 129, 130, 132 and 134."

The motion was adopted.

17.59 hrs.

APPROPRIATION (NO. 2) BILL,** 1969

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : On behalf of Shri Morarji Desai, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1968-69.

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :

"That leave be granted to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1968-69."

The motion was adopted.

SHRI P. C. SETHI : I introduce† the Bill.

On behalf of Shri Morarji Desai, I beg to move† :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

MR. DEPUTY-SPEAKER : Motion moved :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the consolidated Fund of India for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

Shri Limaye :

18 hrs.

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ तीन अनुदानों के बारे में बोलने वाला हूं । सबसे पहले मैं व्यापार मन्त्रालय के बारे में बोलना चाहता हूं पता नहीं व्यापार मन्त्री हाजिर हैं या नहीं क्योंकि वह नोटिस देने के बाद भी नहीं आते हैं । पृष्ठ 2 पर कहा गया है,

An additional provision of Rs. 1.40 lakhs is also required mainly to meet larger expenditure on travelling allowance, over-time allowance and honoraria due to increased activities of the Ministry.

अब इनका जो कार्य बढ़ गया है उस के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहता हूं । जब बजट पर चर्चा हो रही थी तो मैं ने बीट बिल

*The following members also recorded their votes :—
AYES : Shri K. Anbazhagan.
NOES : Shri Sitaram Kesari.

**Published in Gazette of India Extra/ordinary, Part II, section 2, dated 19.3.69.

† Introduced moved with the recommendation of the President.

बैग्ज़ के सम्बन्ध में लिखा था। फिर उस को यहां पर दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्या व्यापार मन्त्री इस बात का खुलासा करेंगे कि जो अमेरिका से 480 चावल गेहूं आदि सामान आयेगा उसको रखने से लिये जो बोरे सरकार इस साल खरीदेगी क्या यह बात सही है कि कुल सरकारी आवश्यकता 1 लाख 25 हजार वेल्स है और उसमें से इस वक्त मिलों के पास 55 हजार वेल्स का स्टाक पड़ा हुआ है जो उन्होंने बेनामी रखा है ? पहले तो इनका सुझा था कि निर-नियंत्रित किया जायगा और कंट्रोल का जो दो सौ रुपया दाम है वह ढाई सौ हो जायगा और उस पर यह खरीदेंगे जिसका नतीजा यह होता कि 1 करोड़ 87 लाख का घाटा सरकार को होता। परन्तु मैंने उस में हस्तक्षेप करके डी-कन्ट्रोल का मामला रुकवा दिया है। लेकिन क्या मन्त्री महोदय दो प्रश्नों का जबाब देंगे जिस की सूचना वित्त मंत्री जी को मैंने एक पत्र के द्वारा दी है। उस में से मैं केवल दो प्रश्न पढ़ता हूँ ताकि समय बचे :

Why the Government should not requisition the mill stocks including that held *Benami* ?

Why the Government should not ask the mills to manufacture wheat mill bags and supply to the Government at controlled price when thay were already manufacturing it price to the price fixed by the Government ?

तो इस का मैं खुलासा चाहता हूँ। 1करोड़ 87 लाख का घाटा होगा इस लिये मन्त्री महोदय मेरे दोनों प्रश्नों का खुलासा करें।

इस के साथ इन्डो नेपाल के बारे में मैंने कितने पत्र लिखे। 1 जनवरी का पत्र है, 3 जनवरी का पत्र है। मैं फिर इस बात को दोहराता कि प्रधान मन्त्री ने मुझको एक पत्र द्वारा आश्वासन दिया था कि व्यापार मन्त्रालय से आपको जबाव आयेगा। प्रधान मन्त्री के ज्वाइंट सेक्रेटरी ने मुझसे जबानी कहा था कि स्मरण-पत्र देने की जरूरत नहीं, पत्र का रहा है। लेकिन उस के बाद तीन स्मरण-पत्र आ चुके है और अभी तक मेरी शंकाओं का कोई खुलासा नहीं हो रहा है। 18 नवम्बर को जो करार हुआ था उस करार के अनुसार 90 लाख रुपये का सिन्थेटिक फैब्रिक आने वाला था और 30 लाख का स्टेनलेस स्टील का सामान आने वाला था। नेपाल का उत्पादन सिन्थेटिक का जितना माल करार के अनुसार आने वाला था उससे तीन गुना ज्यादा हो गया है। यह चोरी से सारा माल आ रहा है। इन का कस्टम आर्डिनेंस आने वाला है। इसलिये विस्तार में इस वक्त बात नहीं करूंगा। लेकिन मेरे पत्रों का न तो जवाब आ रहा है न उस के बारे में कार्यवाही हो रही है। नेपाल के द्वारा हमारा जो निर्यात माल है वह सारा विदेशों को जा रहा है और हमको विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही है। देश चौपट हो रहा है और इन का भूत पूर्व व्यापार मन्त्रालय तथा वर्तमान विदेश व्यापार मन्त्रालय सो रहा है, गहरी निद्रा में, कुंभकर्ण की नींद में पड़ा हुआ है।

दूसरी मांग के बारे में मुझे यह कहना है जो कि फाइनेन्स मन्त्रालय की मांग है। इनकी पुस्तक में कहा गया है।

To streamline and improve the working of the Central Board of Excise and Customs and the Central Board of Direct Taxes, certain new posts, the details of which are given in the Annexure, were created and filled up during the current year.

To improve the working of the Central Board of Excise and Customs.

इन के कार्य में सुधार लाने के लिये यह अधिक खर्चा कर रहें हैं लेकिन इन का कार्य सुधरने के बजाय खराब होता जा रहा है। आज मैं पूरी ताकत के साथ और सबूत के आधार पर दो बातें कहना चाहता हूँ। यह 1966 की बात है। बर्ड कम्पनी के बारे में कस्टम अधिकारी ने फैसला दिया कि उनको जबर्दस्त जुर्माना देना पड़ेगा। एक करोड़ 30-40 लाख तक का मामला था। उस के बाद अपील में यह लोग गये। मैंने प्रधान मन्त्री को नवम्बर 1966 में चिट्ठी लिखी कि मेरे पास बहुत सबूत है कि उस अपील में सैटल

[श्री मधु लिमये]

बोर्ड के अधिकारियों को वर्ड कम्पनी के द्वारा खरीदा गया है और अपील का फैसला क्या होगा वह मैं अभी से 6 महीने पहले से बतला रहा हूँ। वह 6 महीने पहले मैं ने प्रधान मन्त्री को बतला दिया था।

जब नये चुनाव हो गये और नये वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई आये उसके 24 घंटे पहले इस अपील का फैसला हुआ। मैंने कहा था कि एक करोड़ रुपया माफ होगा लेकिन 1 करोड़ 20 लाख रुपया माफ किया गया। श्री मोरारजी देसाई से मेरी बातचीत हुई। सभी प्रमुख पार्लियामेंट के मदस्यों से हस्ताक्षर करा कर, कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य भी उसमें थे, उन सभी ने मेरे उस मैमोरैंडम पर हस्ताक्षर किये और हम सब लोग मोरारजी भाई से उसे लेकर मिले। उस दिन स्व० श्री अन्नादुराय यहां आये हुये थे और उनके स्वागत में मद्रास हाउस में एक समारोह का आयोजन हुआ था। उस समय मोरारजी भाई ने कहा कि मैं तुम्हारे मैमोरैंडम के आधार पर इस सम्बन्ध में आवश्यक जांच पड़ताल करूंगा और अगर उन अधिकारियों को मैं दोषी पाऊंगा तो सैंट्रल बोर्ड के एक, एक अधिकारी को मैं निकाल दूंगा। यह मोरारजी भाई के शब्द थे ....

श्री प्रेमचन्द वर्मा (हमीरपुर) : मोरारजी देसाई ने यह कहां कहा था कि वह एक, एक जिम्मेदार अधिकारी को निकाल देंगे ?

श्री मधु लिमये : श्री मोरारजी देसाई ने कहा था।

श्री प्रेमचन्द वर्मा : जो उनका स्टेटमेंट है वह मेरे पास है और इस बारे में मैं माननीय सदस्य से ज्यादा जानता हूँ (व्यवधान)

श्री मधु लिमये : यह हल्ला आप लोग क्यों कर रहे हैं मोरारजी भाई को खण्डन करना होगा तो वह करेंगे। बात मोरारजी भाई और मेरे बीच में हुई थी यह बेचारे बीच में क्यों अड़ंगा डाल रहे हैं ?

श्री प्रेम चन्द वर्मा : वहां जलसे में जो उनकी स्पीच हुई है वह मेरे पास है।

श्री मधु लिमये : जलसे में नहीं, मुझ से उन्होंने यह कहा था।

उसके बाद वर्ड कम्पनी सुप्रीम कोर्ट में गई सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वह जो चाहें अपना फैसला करें लेकिन सरकारी स्तर पर यह कार्यवाही कर सकते हैं श्री आनंद और दूसरे जो सदस्य हैं बिलकुल भ्रष्ट लोग हैं। 6 महीने पहले इनके बारे में मैंने जो भविष्य वाणियां की थीं वह सब सही निकली हैं। अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

18.09 hrs.

[Shri Bhandare *in the Chair*]

दूसरी बात मुझे इस सैंट्रल बोर्ड के बारे में यह कहनी है कि बी ओ ए सी वाले एक हवाई जहाज से स्मगलिंग के लिए, तस्कर व्यापार के लिए सोना ले जाते रहे थे। सोने को पकड़ा गया और हवाई जहाज को भी रोक रखा। कस्टम अफसर ने जुर्माना किया। सोने को जब्त कर लिया, ऐयरक्राफ्ट को जब्त कर लिया। मैं ने इस सदन के सामने साबित किया है कि बी ओ ए सी के मैनुएल में अधिकारिक ढंग से इस तरीके की धारा थी जिसमें हिन्दुस्तान के कानूनों को तोड़कर किसी तरह सोना तस्कर व्यापार के लिए ले जाना चाहिये यह बतलाया गया था। जैसा मैंने कहा उसके बारे में मैनुअल में एक प्राविजन है और यह मैंने पढ़कर सुनाया है उस केस में जुर्माना होता है, एयरक्राफ्ट जब्त किया जाता है, सोना जब्त किया जाता है लेकिन फिर सैंट्रल बोर्ड के लोगों के ऊपर दबाव आया। यह अगस्त 1968 की बात है, मैंने प्रधान मन्त्री को पत्र लिखा और बतलाया कि वर्ड कम्पनी के बारे में जो हुआ वही उसमें भी होने वाला है ? मैं ने कहा था कि मैं आजही भविष्यवाणी हूँ यह आनन्द और दूसरे जो भ्रष्ट अधिकारी हैं यह फिर से बी ओ ए सी के बारे में वही करेंगे

जो कि इन्होंने वर्ड कम्पनी के बारे में किया था।

अब पता चला रहा है कि बी ओ ए सी के केस में सैंट्रल बोर्ड के लोगों ने रिश्वत लेकर पैसा खाकर, अंग्रेजों के दबाव में आ कर यह सोना माफ कर दिया। विमान वापस कर दिया है। बी ओ ए सी की मैगजीन में हिन्दुस्तान के बारे में कैसे कार्टून आते हैं यह देखिये। यहां हिन्दुस्तान के पुलिस अधिकारी से अंग्रेज पुलिस अधिकारी कहता है व्यंग में कि :

> "Look, mate nickin my gin's one thing, but half a million quids' werth of gold's a bit bloody ambitious even for you, isn't it,"

यह जानते हैं कि अंग्रेज चले गये, लेकिन आज भी वित्त मन्त्रालय के ऊपर, सैंट्रल बोर्ड के ऊपर अधिकार प्रधान मन्त्री और वित्त मन्त्री का नहीं चलता है, भारत में जो अंग्रेज हाई कमिश्नर हैं, बी ओ ए सी है, उन लोगों का अधिकार चलता है। इतने आप के अधिकारी निकम्मे हो गये हैं। मैंने कहा कि बी ओ ए सी का चार्टर रद्द करो, लेकिन आप की हिम्मत नहीं हुई। खिल्ली उड़ा रहे हैं वह आपकी।

मेरा अन्तिम मुद्दा जिस मन्त्रालय के बारे है वह ट्रांसपोर्ट और शिपिंग मन्त्रालय है। इस में लिखा है कि :

> "Increased expenditure on Telex, telegrams and telephones.
>
> The working of the chartering organization of the Ministry of Transport and Shipping requires extensive use of telex, foreign telegrams and telephones for contacting foreign countries for chartering ships."

शिपिंग विभाग अधिक खर्च के लिये पैसा मांग रहा है, लेकिन कोई सावधानी और जागरूकता नहीं दिखा रहा है। हिन्दुस्तान में जो ब्रोकर्स हैं, जो शिपिंग एजेन्ट्स है उन का करार हुआ करता है विदेशी शिपिंग एजेन्ट्स से और ब्रोकर्स से और उस में तय हुआ है कि उन को जो 1.25 परसेंट कमीशन मिलता है उसका बटवारा होगा। आधा विदेशी लोग रख लेते हैं और आधा कमीशन हम लोगों को मिल जाता है। इस के बारे में नियम है रिजर्व बैंक और वित्त मन्त्रालय के कि भारत का जो ५० परसेंट कमीशन है वह पूरा मिलना चाहिए और विदेशी मुद्रा के रूप में मिलना चाहिये। इस के बारे में क्या चल रहा है और श्री रघुरामैया का मन्त्रालय क्या करता है। वैसे तो सभी शिपिंग एजेन्ट्स और ब्रोकर्स बेईमानी कर रहे है, लेकिन एक सबूत मैंने पकड़ा है, वह दस्तावेज मैं रखना चाहता हूं। इस में इन्टरनेशनल चार्टरिंग सर्विस इन्कोरपोरेटेड नाम की कम्पनी भारत की एक कम्पनी को लिखती है कि :

Mr. Kamath,

Please note an agreement was made with Mr. Vasant and Naresh Kotak so that Jairam Dass only receive 40% instead of 50% Please contact them for confidential details.

Sd. (M. I. De Luca Jr)

जब कानून है कि आधा मिलना चाहिये और विदेशी मुद्रा में मिलना चाहिये तो यह विदेशी कम्पनी कैसे लिखती है कि कोई हम लोगों में समझौता हुआ है, इस लिये 10 परसेंट वहीं रहेगा ?

श्री जार्ज फरनेन्डीज़ (बम्बई-दक्षिण) : इसे सभा पटल पर रखा जाये।

श्री मधु लिमये : यह दस्तावेज है, इसको रखने के लिए मैं तैयार हूं।

तेजा का मामला आपको मालूम है। तेजा के समय जो बड़े पैमाने पर हुआ करीब करीब वही आज ब्रोकर्स और शिपिंग एजेन्ट्स के सभी लोग कर रहे है। जिस कम्पनी का मैं उल्लेख कर रहा हूं उसका 4 करोड़ रुपये का धन्धा है। मैं ने एक उदाहरण पकड़ा है। 10 प्रतिशत यह रख लेते हैं। क्या मतलब हुआ ? 4 करोड़ रुपये पर 20 प्रतिशत अर्थात् 80 लाख रुपये का घाटा हमें विदेशी मुद्रा का हो रहा है। मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं ताकि इस देश

[श्री मधु लिमये]

का निर्यात व्यापार बढ़े, विदेशी मुद्रा बढ़े और चौधरी साहब मानेंगे कि अगर वित्त मन्त्रालय को गरीब किसान के ऊपर लगान बढ़ाने और फर्टिलाइजर पर ड्यूटी और पम्पिंग सैट पर उत्पादन शुल्क लगाने के लिये मजबूर नही होना है तो इसके लिए आवश्यक है कि इस तरह की विदेशी मुद्रा की चोरी और करों की चोरी की रोका जाय ।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : सभापति महोदय, श्री लिमये जी ने जो नेपाल के सम्बन्ध में कहा बिलकुल सही कहा । नेपाल से हमारे यहां स्टेनलैस स्टील के बरतन आते हैं, रीलें आती हैं, ट्रान्सिस्टर आते हैं, घड़िया आती हैं, कपड़े आते हैं, नाइलोन के कपड़े आते हैं ऊनी कपड़े आते हैं, फाउन्टेनपेन आते हैं । हमारे यहां से लोहा चोरी से जाता है, दालें जाती हैं बैटरी जाती है, मिट्टी का तेल जाता है, कडवा तेल जाता है, टायर जाते हैं, ट्यूबें जाती हैं । इस तरह की बहुत सी चीजें जाती हैं । जो व्यापार कानूनन होना चाहिये, वह कानूनन व्यापार नही हो रहा है । अभी अखबारों मे निकला था कि मुजफ्फरपुर में कुछ सामान पकड़ा गया है । और भी बहुत सा सामान कई बार पकड़ा जाता है । उधर से गांजा आता है और वह बम्बई तक चला जाता है ये रीलें जो आती है वह बम्बई चली जाती हैं ---------- (घंटी बजी) जब उधर से मैम्बर बोलते है तो आप घण्टी नही बजाते हैं और हमको दो मिनट के लिए भी बोलने नहीं देते है । मैं यहां 20 साल से मैम्बर हूँ । जितना समय आपने उनको दिया हैं, उतना हमें भी देना चाहिए । चेयर पर बैठ कर आप हमारे साथ अन्याय करते हैं हमें कह लेने दीजिये - - -

सभापति महोदय : जिन्होंने नोटिस दिया है, उन्हीं को बोलने दिया जा रहा है और उन्हीं को बोलने का अधिकार है ।

श्री विभूति मिश्र : या तो आप नोटिस के आधार पर चलें या फिर इस आधार पर चलें कि आपकी आई को कैच किया जाए । अगर नोटिस के आधार पर चलना है तो आखें बन्द कर लीजिये । कोई कानून तो यहां होना चाहिये ।

हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि नेपाल से वर्षों सा व्यापार जो गैर वाजिब तरीके से हो रहा है, वह बन्द हो । उधर से स्टेनलैस स्टील जब चोरी छिपे आ जाता है तो इसका नतीजा यह होता है कि जो यहां बनता है और उसका जो व्यापार होता है वह कम हो जाता है । और यहां का बना हुआ महंगा पड़ रहा है । नेपाल से जो आता है वह सस्ता पड़ता है । इस कारण से आपका जो व्यापार है वह ठप्प हो रहा है, चौपट हो रहा है । इसलिये यह जरूरी है कि नेपाल के साथ आपने जो समझौता किया है उसके साथ साथ आप नेपाल बोर्डर पर कड़ाई बरतें ।

श्री लिमय ने जो कहा है वह देश भक्ति की भावना से प्रेरित हो कर कहा है देश भक्ति की बात उन्होंने बताई है । सरकार को उधर ध्यान देना चाहिये । यह कोई पार्टी का सवाल नही है । यह देश का सवाल है । जहां देश का सवाल हो, सरकार को उस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये । अगर सरकार ने उधर ध्यान नहीं दिया तो इस देश का व्यापार चौपट हो जायगा ।

SHRI RANGA (Srikakulam) : We are talking about the additional provisions and funds for the Commerce Ministry. My complaint is that this Ministry is not discharging its duty in regard to promotion of exports. The hon Minister must have received representations from tobacco growers not only in Guntur in Andhra but also from Gujarat and Mysore. They are having a very bad time now. For a long time too, year after year, this trouble comes upon them. They do not find market. Sometime back we were told that Soviet Russia and other countries would take large quantities of tobacco from us and salve our trouble but their orders also had been slackening during this year. There

are two great monopoly buyers. One is the ILTD from Western Europe and England. The other is from the totalitarion countries headed by Soviet Russia. They have their own methods of monopoly purchases. We thought that they would buy through the STC but they went far beyond that. They made our people compete with one another in order that the prices quoted may be even uneconomical. What do the Government propose to do to help them ? Every year they go on making pilgrimages. Last year I wrote a letter to the Commerc Ministry in December. When did I get a reply ? Rightly, many friends complain about Government's delays. I am supposed to be holding an important position in this House. Still they have taken more than three months to reply. I wrote about the need for the Commerce Ministry to take expeditious steps to push up the sales and export of tobacco I have been making a constructive suggestion that they should utilise the State Trading Corporation as well as the Reserve Bank of India and the Warehousing Corporation and all the other authorities that they have brought into existence in order to ensure that all these stocks which have been built up and hoarded up should be taken over and, as a collateral security against them, credit should be advanced to the merchants as well as the kisans to the tune of at least 50 per cent of the estimated sale value and, if possible, 75 per cen of the sale value, so that the growers as well as the merchants will not be put to trouble and will not suffer so much as they have been suffering till now, for want of credit, for want of eworking capital, for the next crops. Inthere meanwhile, these stocks would be The and they need not be wasted at all. for ihe Government can be searchinr, for the market. Uufortunately, howe been verus, the Commerce Ministry has Theyvgy, very remiss in this directinonorder to say [they want more money world. Is isend their people round theh at they go rout for joy-ride ? I ake it wtork in order to get into touch with goodvarious people who are interested in thee purchase of our raw material from here and also the manufactured goods. Recently, they have been paying some attention to the export of raw and manufactured goods, but what about the earlier customary exports that we were having ? I want the Government to give special consideration in regard to this matter and see to it that they take it up as one of their most important, principal functions to push up the exports of tobacco, ensure earlier exports also and see to it that the markets that are available are always assured for the tobacco growers, and they are given the necessary accommodation from the Reserve Bank, from the State Banks and other banks and in that way they come to the rescue of these people.

Thank you.

Shri Kanwar Lal Gupta *rose-*

MR. CHAIRMAN : Order, order. I may read the following for the benefit of the hon. Member and for the benefit of the House :

> "The Speaker may, in order to avoid repetition of debate, require members desiring to take part in discussion on an Appropriation Bill to give advance intimation of the specific points they intend to raise, and he may withhold permission for raising such of the points as in his opinion appear to be repoetitions of the matter discussed on a demand for grant or as may not be of sufficient public importance."

Several Hon. Members *rose-*

MR. CHAIRMAN : Please take your seats first. I can appreciate your anxiety. But then, why is it that when they wanted to speak, as Shri Madhu Limaye has done, they did not give notice ?

SHRI RANGA : I, as the Leader of a party in Opposition gave enough notice and I gave it to the Deputy-Speaker.

MR. CHAIRMAN : I quite appreciate your position as the Leader of the Opposition, but can he persuade me to go against this rule ? *(Interruption)*.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, इसमें एक्सटर्नल अफेयर्ज मिनिस्ट्री के लिये अतिरिक्त ग्रांट मांगी गई है ?

सभापति महोदय : कौन सी डिमान्ड है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : मैं नम्बर बता सकता हूं। —मैं समझता हूं कि नम्बर की कोई जरूरत नहीं है। मेरा कहना यह है कि दूसरे देशों में हमारे जो एम्बैसडर्ज और हाई कमिश्नर्ज हैं, उन्हें दुनिया के सामने इस देश की जो तस्वीर रखनी चाहिए, वे लोग वह तस्वीर नहीं रख रहे हैं। वे समझते हैं कि उनका काम सिर्फ यही है कि दावतों में टोस्ट प्रोपोज कर दें। इसके अलावा हम यह भी देखते हैं कि जो लोग दूसरे देशों में तीन चार साल रहते हैं, वे उस अरसे में इम्पोर्टिड चीजें इकट्ठी करते रहते हैं और हिन्दुस्तान वापस आते वक्त उन्हें अपने साथ ले आते हैं। इन दो कामों के अलावा कोई तीसरा काम वे नहीं करते हैं।

मुझे दो बातों के बारे में मालूमात हुई हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन का जवाब दें। एक सज्जन को सरकार ने यू० एन० ओ० में भेजा था। आज वह करीब सात आठ महीनों से वहां है। मैं ने सुना कि वह सज्जन धर्म तेजा से मिलने के लिए कोस्टारीका भी गये थे। वह धर्म तेजा को मिलने क्यों गये, किसने भेजा, आया सरकार ने भेजा या खुद गये, यह एक काफी टाक आफ दी टाउन है। मैं चाहता हूं कि इस के बारे में जो फैक्ट्स हैं उनका पता लगाया जाय और धर्मतेजा का क्या हुआ यह भी मैं जानना चाहता हूं।

दूसरे, क्या यह सही है कि एक एम्बैसेडर जो रिटायर्ड फौजी अफसर हैं उन्होंने आप से यह परमीशन मांगी है कि वह जहां एम्बैसेडर है वहां की एक लड़की से जो 24 साल की है उस से शादी करना चाहते हैं। उस के लिये उन्होंने परमीशन मांगी है।

एक माननीय सदस्य : उस में आपको क्या एतराज है।

श्री कंवर लाल गुप्त : यह तो सरकार ने मना कर रखा है। इसीलिए परमीशन की जरूरत है ... (व्यवधान)

इसी तरीके से एक प्वाइंट और मैं कहना चाहता हूं जो चौधरी रणधीर सिंह जी ने कहा कि जवानों की सुविधाएं और एलोवेंसेज ज्यादा होने चाहिएं। अभी अफसरों में और जवानों में बहुत भेद है। जो बार्डर एरिया में लोग रहते हैं हमारे सिपाही और जवान और दूसरे अफसर उन की सुविधाओं में बहुत फर्क है, खाने में, एलावेंस में, फैमिली एलावेंस में बच्चों की पढ़ाई में, इन में दोनों में बहुत अन्तर है मैं चाहता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में जानकारी करके वह जो भेद है दोनों का उसे कम से कम करे।

आखीरी बात कह कर मैं समाप्त करूंगा। रिटायर्ड मिलिटरी परसोनेल्स हमारे देश में बहुत ज्यादा तादात में हैं और सरकार ने उनके रिहैबिलिटेशन की जिम्मेदारी ली है लेकिन वह राज्य सरकारों पर डाल दी है। मुझे यह मालूम हुआ है कि उन का एक एसोसिएशन और यूनियन भी बना हुआ है। अगर सरकार ने इस पर कोई फौरी कदम नहीं उठाया तो इसके घातक नतीजे निकल सकते हैं। मैं मांग करूंगा कि उन के रिहैबिलिटेशन के लिये जो लाखों की तादात में है एक कमीशन सरकार अप्वाइंट करे जो राज्य सरकारों से मिल कर के और जितने पैसे आपके पास हैं उनको देखते हुए एक कान्क्रीट और स्पेसिफिक स्टेप उठाये ताकि यह जो डिससेटिस्फैक्शन है यह मिलिटरी के अंदर भी न घुस जाय क्यों कि अभी तक जो हो रहा है वह कुछ भी नहीं हो रहा है। आप ने राज्य सरकारों पर डाल रखा है। राज्य सरकारों के पास फंड्स बहुत थोड़े हैं और उनकी क्वालीफिकेशन भी उन के मुताबिक नहीं है। जैसे सरकार भी रेलवे में या डिफैंस प्रोडक्शन के कारखाने में उन को प्रेफरेंस नहीं देती। तो मेरी मांग यह है कि आप सरकारी कारखानों में उन को प्रेफरेंस दें और इस सम्बन्ध में उनके रिहैबिलिटेशन के लिए एक कमीशन बैनायें।

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor): Sir, it is time to take up the half-hour discussion. The agenda says it will be taken up at 6.30 or as soon as the preceding items are disposed of, whichever

is earlier. 6.30 is earlier. Already this has been postponed once.

MR. CHAIRMAN : I have read it. We can take up the half-hour discussion after the passing of this Bill.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, यह जल्दी काम नहीं हो पायेगा । जवाब कल आए । कोई फर्क नहीं पड़ता है । कोई आसमान नहीं टूटने वाला है ।

MR. CHAIRMAN : The hon. minister.

SHRI P. C. SETHI : The hon. Member, Shri Madhu Limaye, has raised many points during the course of this debate. As far as the case of Bird & Company is concerned, I would only point out at this stage that it is *sub judice*.

श्री मधु लिमये : न्यायालय के विचाराधीन सबजुडिस क्या है । सरकारी कार्यवाही अफसर के खिलाफ सबजुडिस नहीं है, यह मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, लेकिन उसका और सरकारी एक्शन लेने का कोई सम्बन्ध नहीं ।

SHRI P. C. SETHI : So, we will not be able to take any action until after the the receipt of the judgment of the Supreme Court. Then, as far as BOAC is concerned, it is not possible for me to spell out the full details.

श्री मधु लिमये : कब जवाब देंगे, कल दीजिये ।

SHRI P. C. SETHI : There is a short notice question with regard to this.

SHRI MADHU LIMAYE : Are you admitting that ?

SHRI P. C. SETHI : Yes. During that short notice question we shall be able to answer this particular point.

So far as the chartering organisations are concerned, the Delhi brokers are not appointed by this chartering organisation. They are appointed by the foreign brokers as the local representatives and whatever commission accrues to them.....

श्री मधु लिमये : विदेशी मुद्रा से फारन-एक्सचेन्ज से आपका सम्बन्ध है ।

SHRI P. C. SETHI : Whatever commission is given to them is to be paid by the parties concerned and the chartering organisation does not come into the picture. It is in view of this agreement.....

श्री मधु लिमये : मेरा सवाल बिलकुल दूसरा था—विदेशी मुद्रा भारत में आनी चाहिये—यह रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी है, शिपिंग मन्त्रालय की जिम्मेदारी है । नोटिस देने का क्या फायदा है, ये तैयारी करके क्यों नहीं आते हैं । मैं चाहता हूँ कि मेरे सवाल का जवाब दिया जाय । विदेशी मुद्रा की जिम्मेदारी किस की है - आपकी है या नहीं, रिजर्व बैंक की है या नहीं ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) यह कौन सा तरीका है, इसको नहीं मानेंगे । अगर यह बोल सकता है तो हम डबल जोर से बोलेंगे...

श्री मधु लिमये : यह बिलकुल ठीक तरीका है...(*व्यवधान*)...

श्री रणधीर सिंह : हमें सरमनाइज न कीजिये । I take it seriously.

श्री मधु लिमये : हमें एक-एक मुद्दे का जवाब दिया जाय ।

MR. CHAIRMAN ; I would request the hon. Member to resume his seat.

SHRI RANDHIR SINGH : Sir, I take it seriously. I am not going to yield.

MR. CHAIRMAN : Take your seat please.

SHRI RANDHIR SINGH : No, no, Sir. I am not taking my seat.

हर रोज का एक मजाक बन गया है । No, no (*Interruption*)

Mr. CHAIRMAN : The hon. Minister is answering. Please take your seat. You have not raised the point of order. Please take your seat first.

श्री रणधीर सिंह : शराफत से इखलाक से भलेमानसपन से बात करे.....

SHRI MADHU LIMAYE : **

श्री रणधीर सिंह : What is this ? ** यह क्या तरीका है ये मिनिस्टर को कोई बच्चा समझते हैं । हम इसको बिलकुल नहीं मानेंगे ।

श्री मधु लिमये : मैं आप से जवाब नहीं मांग रहा हूँ, आप क्यों बोल रहे हैं ?

श्री रणधीर सिंह : यह क्या तरीका है मास्टर की तरह बर्ताव कर रहे हैं ।

Sir, through you I give him a warning. He should behave.

श्री मधु लिमये : कौन वार्निंग देता है, ** तुम्हारी वार्निंग की ।

SHRI RANDHIR SINGH : **

श्री मधु लिमये मैं आप ने बात नहीं कर रहा हूँ, मंत्री से बात कर रहा हूँ ।

श्री रणधीर सिंह :**What is this ? ...(व्यवधान)...

SHRI MADHU LIMAYE : **

श्री रणधीर सिंह : अगर इस तरह से बिहेव किया **

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) Sir, I would request that these words may be expunged from the record.

SHRI N. K. SOMANI (Nagaur): Certain words have been used which are extremely unparliamentary. They should not have been used. They should be expunged. (*Interruption*). You should give a ruling.

श्री मधु लिमये : इनके बीच में पड़ने की क्या जरूरत थी ।

श्री रणधीर सिंह : एक-एक लाख वोट से इन लोगों को हरा कर आये हैं । इन की जमानतें जब्त कराई हैं । सारी पार्टी के चार-पाँच मेम्बर है, क्या समझते हैं अपने आपको ?

MR CHAIRMAN ; I would request the hon. Member to resume his seat.

SHRI RANDHIR SINGH : What does he think of himself ? He should be have properly. Otherwise, I will teach him a lesson.

MR. CHAIRMAN : If you do not listen to me and if there is no order in the House, I will adjourn the House.

SHRI RANDHIR SINGH : That is all right. But he should beave.

MR. CHAIRMAN : The rule is that if at all a member gives notice.....

SHRI RANDHIR SINGH : There is a limit to everything.

MR CHAIRMAN : Why can't you listen first, if you are not a aware of these rules ?

SHRI RANDHIR SINGH: I am listening. But our patience is exhausted.

MR. CHAIRMAN : If a member gives notice, he can ask the Minister concerned to give the reply.

SHRI RANDHIR SINGH : But he must behave.

MR. CHAIRMAN : Why can you not listen ?

SHRI RANDHIR SINGH : If you cannot make him behave, I will make him behave.

श्री मधु लिमये : ये आपके साथ हुज्जत क्यों कर रहे हैं ।

SERI RANDHIR SINGH : **

श्री मधु लिमये : देखिए आप इनको निकाल दीजिये ।

** Expunged as ordered by the Chair.

SHRI N. K. SOMANI : Certain bad words have been used. They should not be allowed to remain on the record. Whatever he has said in his heat and temper should be expunged. It is certainly very intermperate.

श्री रामावमार शास्त्री (पटना): यह बर्दाश्त नहीं होगा । ऐसी कोई भी बात यहां पर नहीं कहनी चाहिये ।

SHRI RANDHIR SINGH : I Will teach him a lesson, I tell you.

श्री कंवर लाल गुप्ता : आप बाद में इसको देखकर एक्सपंज कर दीजिए ।

MR. CHAIRMAN : We shall see the record and do the needfull. Whatever is to be expunged will be expunged.

श्री रणधीर सिंह : ये मिनिस्टरों को गोली देने में अपनी शान समझते हैं ।**

What does he think of himself ? There is a limit.

SHRI P. C. SETHI : Whatever information I have with me with the regard to this I have already passed on but if the hon. Member has in his mind the letter which he has recently written, perhaps yesterday, to the Prime Minister and the Deputy Prime Minister, that letter is being looked into.

SHRI RANDHIR SINGH : Do not reply to him.

SHRI N. K. SOMANI : What is this ?

श्री मधु लिमये : ये बर्दास्त के बाहर जा रहे हैं । आप इनको सदन से निकाल दीजिए ।

SHRI RANDHIR SINGH : He is a cheap agitator.

MR. CHAIRMAN : If yon do not keep quiet, I will be compelled to name you.

SHRI SONAVANE : They are taking to bullying tactics.

SHRI M. N. REDDY (Nizamabad) : On a point of order. I want to ask you whether all these unparliamentary and indecorous utterances have been removed.

MR. CHAIRMAN : I have already observed that after seeing the record, the unparliamentary words will be expunged. You have not heard that and therefore you have raised the point of order.

SHRI P. C. SETHI : As far as the B twills are concerned, the DG S&D, who has been the main buyer of these twills, has not gone into the open market for this but is purchasing it at the controlled price.

श्री प्रकाश वीर शास्त्री (हापुड़) : सभापति महोदय, आप कोई पमम्परा तो बनाइये या इस तरह से एक्सपंज ही करते रहेंगे । —(व्यवधान)...मेम्बर्स की तो जिम्मेदारी है लेकिन चेयर की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है । मैं पिछले दस वर्षों से इस भवन का सदस्य हूँ लेकिन पार्लमेंट का जितना स्तर अब धीरे-धीरे गिरता चला जा रहा है उसको देख कर सारे लोग हंसते हैं जो कि यहां पर देखने के लिए आते हैं । आपको यहां की परम्पराओं को सम्हालना चाहिए । यह संसद इस देश की सबसे बड़ी संस्था है । यहां यदि इस तरह से गाली-गलौज होगा तो फिर गांव की एक चौपाल में और इस पार्लमेंट में क्या अन्तर रह जायेगा ?

SHRI CHENGALRAYA NAIDU : But this has to be observed by everybody.

SHRI DWAIPAYAN SEN (Katwa) : Shri Madhu Limaye said **

श्री मधु लिमये : मुझे सख्त एतराज है । मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने केवल यही कहा था कि मेरे प्रश्नों का जवाब दीजिए । इसके अलावा मैंने एक वाक्य भी नहीं कहा था ।

श्री कंवरलाल गुप्त : आपको क्यों गुस्सा आ गया ?

SHRI DWAIPAYAN SEN : He started that thing..... *(Interruption)*

** Expunged as ordered by the Chair.

MR. CHAIRMAN : Every Member is quite capable. Why is Shri Gupta pleading on behalf of evevybody ? They do not require his help or anyone else's help.

SHRI P. C. SETHI : As far as the question of Ind-Nepalese Treaty is concerned, the Customs (Amendment) Bill is coming up and we shall be discussing that point thoroughly. It would not be possible for me to go into the details with regard to the particular point raised by the hon. Membpr.

I am grateful to Professos Ranga and Shri Kanwar Lal Gupta for giving suggestions which would certainly receive the utmot consideration.

श्री मधु लिमये : बी ट्वील बेग्ज के बारे में जवाब देना चाहिए कि सरकार रिक्वीजीशन करेगी या नहीं। कन्ट्रोल दाम से आप बोरे रिक्वीजीशन करेंगे या नहीं...(व्यवधान)...मैं व्यापार मन्त्री से जवाब चाहता हूँ।

श्री प्र० चं० सेठी : मैं जवाब दे चुका हूं।

श्री मधु लिमये : फूड कारपोरेशन कन्ट्रोल दाम से अधिक पर खरीद रहा है, तो क्या आप कन्ट्रोल दाम से रिक्वीजीशन करेंगे ?

MR. CHIRMAN : He is answering.

SHRI P. C. SETHI : I have already answered.

SHRI MADHU LIMAYE : I do not want an answer from you. I want an answer from the Minister of Foreign Trade.

SHRI P. C. SETHI : I am answering on behalf of Government.

MR. CHAIRMAN : Now, the question is :

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 1968-69, be taken into consideration."

The motion was adoped

MR. CHAIRMAN : Now, we take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

The question is :

"That clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title stand part of the Bill."

The motion was adopted

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Tite were added to the Bill.

SHRI P. C. SETHI : I move :

"That the Bill be passed"

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed"

The motion adopted

18.41 brs.

HALF-AN-HOUR DISCUSSION

Completion of Bokaro Steel Project

SHRI CHENGALRAYA NAIDU (Chittoor) : Mr. Chairman, Sir, the Bokaro Steel Plant which is being set up with the Russian help has considerably been delayed. In the way in which it is proceeding, I fear, it will be delayed by at least two to three years.

There are two reasons for this delay, in my opinion, and one is that Russia does not want India should develop speedily and the other is that they want to put continuous pressure on India so that India may help them in the international sphere and also act according to their wishes. Bothways, they have succeeded. They are putting pressure on every matter and also indulging in our internal affairs too.

As the House is aware, the Railway Wagons Deal with Russia which was considered and finalised long ago is still hanging on. May I ask the Minister when it will be completed ? About six months back, thet hen Minister said that there was nine months delay. Will the Minister tell us whether at least within these 9 months the project will be completed or whether he will come forward for another six